भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग I, खंड I में प्रकाशनार्थ

भारत सरकार

वाणिज्य विभाग

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

व्यापार उपचार महानिदेशालय

चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग,

5, संसद मार्ग, नई दिल्ली - 110001

जांच शुरुआत अधिसूचना

मामला सं. एडी (ओआई)-034/2026

दिनांक : 23 जून 2026

विषय: चीन PR से "सोडियम नाइट्राइट" के आयात के संबंध में एंटी-डंपिंग जांच शुरू करना।

1. **फा. सं.6/34/2026- डीजीटीआर**: समय-समय पर संशोधित कस्टम्स टैरिफ एक्ट, 1975 (जिसे आगे 'एक्ट' कहा जाएगा) और समय-समय पर संशोधित कस्टम्स टैरिफ (एंटी-डंपिंग ड्यूटी की पहचान, मूल्यांकन और वसूली के नियम, 1995) (जिसे आगे 'नियम' कहा जाएगा) को ध्यान में रखते हुए, दीपक नाइट्राइट लिमिटेड ('DNL') (जिसे आगे 'आवेदक' कहा जाएगा) ने चीन PR (जिसे आगे 'संबंधित देश' कहा जाएगा) से "सोडियम नाइट्राइट" (जिसे आगे "संबंधित सामान" या "विचाराधीन उत्पाद" कहा जाएगा) के आयात के संबंध में एंटी-डंपिंग ड्यूटी जांच शुरू करने के लिए नामित प्राधिकरण (जिसे आगे 'प्राधिकरण' कहा जाएगा) के समक्ष एक आवेदन दायर किया है।

2. आवेदक ने आरोप लगाया है कि चीन से संबंधित सामान के डंप किए गए आयात से घरेलू उद्योग को काफी नुकसान हो रहा है और उसने संबंधित देश से इन सामानों के आयात पर एंटी-डंपिंग ड्यूटी लगाने का अनुरोध किया है।

(क) विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी)

3. जिस प्रोडक्ट की बात हो रही है, वह "सोडियम नाइट्राइट" (SNI) है।

4. SNI एक इंडस्ट्रियल केमिकल है जो ठोस या लिक्विड रूप में बेचा जाता है। इसका कोई दूसरा केमिकल नाम नहीं है। यह सफ़ेद से हल्के पीले रंग का क्रिस्टल जैसा पाउडर, दानेदार, परतदार या ब्रिकेट जैसा ठोस होता है जो पानी में आसानी से घुल जाता है और नमी सोखने वाला (हाइग्रोस्कोपिक) होता है, लेकिन आम ऑर्गेनिक सॉल्वैंट्स में नहीं घुलता।

5. इस प्रोडक्ट को कस्टम्स टैरिफ एक्ट, 1975 के चैप्टर 28 के तहत सब-हेडिंग 28341010 में रखा गया है। कस्टम्स क्लासिफिकेशन सिर्फ़ जानकारी के लिए है और यह इस प्रोडक्ट के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।

6. इस प्रोडक्ट को मापने की तय यूनिट मीट्रिक टन (MT) या किलोग्राम (Kg) है।

7. इस जांच में शामिल पक्ष, जांच शुरू होने की तारीख से 15 दिनों के भीतर PUC/PCN कार्यप्रणाली के दायरे (यदि कोई हो) पर अपनी टिप्पणी दे सकते हैं।

(ख) <u>समान वस्तु</u>

8. आवेदक ने कहा है कि आवेदक द्वारा बनाए गए सामान और संबंधित देश से एक्सपोर्ट किए गए सामान में कोई अंतर नहीं है। आवेदक द्वारा बनाया गया प्रोडक्ट और संबंधित देश से इम्पोर्ट किया गया प्रोडक्ट कई मामलों में एक-दूसरे के बराबर हैं, जैसे कि फिजिकल विशेषताएं, बनाने की प्रक्रिया और टेक्नोलॉजी, काम और इस्तेमाल, प्रोडक्ट की खासियतें, कीमत, डिस्ट्रीब्यूशन और मार्केटिंग, और संबंधित सामान का टैरिफ क्लासिफिकेशन। ये दोनों तकनीकी और कमर्शियल तौर पर एक-दूसरे की जगह इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ग्राहक इन दोनों का इस्तेमाल एक-दूसरे की जगह कर रहे हैं। इसलिए, इस जांच को शुरू करने के मकसद से, घरेलू इंडस्ट्री द्वारा बनाए गए संबंधित सामान को, संबंधित देश से बनाए और इम्पोर्ट किए गए प्रोडक्ट के " समान वस्तु " (like article) के तौर पर माना जा रहा है।

(ग) <u>संबंधित देश</u>

9. यह जांच चीन (PR) से विचाराधीन उत्पाद की कथित डंपिंग के संबंध में है।

(घ) <u>जांच की अवधि</u>

10. आवेदक ने 1 अप्रैल 2025 से 31 दिसंबर 2025 (9 महीने) की अवधि को जांच की अवधि के रूप में प्रस्तावित किया है। हालाँकि, अथॉरिटी ने 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक की अवधि को जांच की अवधि माना है, जो 12 महीने की अवधि है। नुकसान की अवधि 2022-23, 2023-24, 2024-25 और POI शामिल हैं।

(ड़) <u>घरेलू उद्योग और स्थिति</u>

11. कस्टम टैरिफ (एंटी-डंपिंग कर्तव्य की पहचान, अवशेष और नुकसान का प्रदर्शन) नियम, 1995 का नियम 2(बी) घरेलू उद्योग को इस प्रकार दर्शाया गया है: -

"घरेलू उद्योग" का मतलब है वे घरेलू उत्पादक जो कुल मिलाकर वैसी ही वस्तु के निर्माण और उससे जुड़ी किसी भी गतिविधि में शामिल हैं, या जिनका उस वस्तु का सामूहिक उत्पादन, उस वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा है; सिवाय तब जब ऐसे उत्पादक कथित तौर पर डंप की गई वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से जुड़े हों या खुद उसके आयातक हों–ऐसे मामलों में "घरेलू उद्योग" का अर्थ बाकी उत्पादकों से माना जा सकता है।

12. यह आवेदन दीपक नाइट्राइट लिमिटेड ('DNL') द्वारा दायर किया गया है। कच्छ केमिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने इस आवेदन का समर्थन किया है।

13. आवेदक ने भारत के अन्य उत्पादकों के बारे में जानकारी दी है। आवेदक और समर्थक के अलावा, भारत में तीन अन्य उत्पादक हैं - a) नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड b) पंजाब केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड c) राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड। आवेदक ने यह दिखाने के लिए सबूत पेश किए हैं कि राष्ट्रीय केमिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने SNI सहित कई औद्योगिक रसायनों का उत्पादन बंद कर दिया है, क्योंकि यह काम फायदेमंद नहीं रहा और सस्ते आयात की वजह से ऐसा हुआ।

14. आवेदक ने प्रमाणित किया है कि उसका संबंधित देश के किसी निर्यातक या संबंधित सामान के किसी आयातक से कोई संबंध नहीं है।

15. रिकॉर्ड पर उपलब्ध जानकारी के आधार पर, अथॉरिटी इस बात से संतुष्ट है कि आवेदक नियम 2(b) के तहत घरेलू उद्योग की परिभाषा में आता है। यह आवेदन नियम 5(3) के तहत 'स्टैंडिंग' (पात्रता) की शर्तों को पूरा करता है।

(च) <u>कथित डंपिंग का आधार</u>

<u>क. सामान्य मूल्य।</u>

16. आवेदक ने चीन के प्रवेश प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15(a)(i) का हवाला दिया है और यह दावा किया है कि चीन पीआर को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में माना जाना चाहिए और चीन के उत्पादकों को यह दिखाने के लिए निर्देशित किया जाना चाहिए कि उत्पाद और बिक्री के मामले में उद्योग में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियाँ प्रचलित हैं। जब तक चीनी उत्पादक यह नहीं दिखाते कि ऐसी बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियाँ प्रचलित हैं, उनके साधारण मूल्य को एंटी-डंपिंग नियमों की परिशिष्ट- I की धारा 7 और 8 के अनुसार निर्धारित किया जाना चाहिए।

17. आवेदक ने बताया कि उन्होंने यह पता लगाने की कोशिश की कि जिस उत्पाद पर विचार किया जा रहा है, उसे बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में इन देशों के उपभोक्ताओं को किस कीमत पर बेचा जा रहा है (यानी घरेलू मूल्य) या तीसरे देश में उत्पादन की लागत क्या है। वास्तविक बिक्री मूल्य का कोई सत्यापित सबूत सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं था। आवेदक ने यूरोपीय संघ से आयात की कीमत के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित किया है। आवेदक ने दावा किया है कि यूरोपीय संघ से होने वाले आयात की मात्रा महत्वपूर्ण है और यह पूरे हानि अवधि में फैली हुई है। चूंकि यह कीमत CIF एक्सपोर्ट प्राइस है, इसलिए इसे समुद्री फ्रेट, समुद्री बीमा, पोर्ट हैंडलिंग चार्ज, क्रेडिट लागत और इन्वेंटरी रखने की लागत जैसे खर्चों के हिसाब से एडजस्ट किया गया है। हालांकि, शुरुआत के लिए, DG सिस्टम्स के ट्रांजैक्शन वाइज डेटा पर भरोसा किया गया है, जो दिखाता है कि पीओआई के दौरान यूरोपीय संघ से आयात केवल कुल आयात का 1% है। चूंकि यूरोपीय संघ से आयात मात्रा में बहुत कम है, इसलिए इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता।

18. चूंकि सामान्य मूल्य किसी अन्य विधि के आधार पर निर्धारित नहीं किया जा सकता, इसलिए सामान्य मूल्य भारत में भुगतान किए गए या देय मूल्य के आधार पर उचित बिक्री और प्रशासनिक खर्च और भारत में मुनाफे के समायोजन के साथ निर्धारित किया गया है। इच्छुक पार्टियों को सलाह दी जाती है कि वे अपने सुझाव प्रस्तुत करें और

सामान्य मूल्य निर्धारण के लिए अपनाई जाने वाली विधि के संबंध में उचित रूप से सबूतों के साथ दावे प्रस्तुत करें।

ख. निर्यात कीमत

19. विचाराधीन प्रोडक्ट की एक्सपोर्ट प्राइस, DG सिस्टम डेटा में बताई गई CIF प्राइस को ध्यान में रखकर तय की गई है। इसमें समुद्री माल-भाड़े, समुद्री बीमा, हैंडलिंग चार्ज, पोर्ट हैंडलिंग चार्ज, कमीशन और क्रेडिट कॉस्ट के लिए एडजस्टमेंट किए गए हैं।

ग. पाटन मार्जिन

20. सामान्य मूल्य और निर्यात मूल्य की तुलना एक्स-फ़ैक्ट्री स्तर पर की गई है, जिससे प्रथम दृष्टया यह पता चलता है कि डंपिंग मार्जिन 'डी-मिनिमिस' (न्यूनतम) स्तर से ऊपर है और संबंधित देश से निर्यात किए जा रहे उत्पाद के मामले में यह काफ़ी ज़्यादा है। इस प्रकार, प्रथम दृष्टया ऐसे सबूत मौजूद हैं जिनसे पता चलता है कि संबंधित देश के निर्यातकों द्वारा भारतीय बाज़ार में संबंधित देश के उत्पाद की डंपिंग की जा रही है।

(छ) क्षति और कारणात्मक संबंध

21. आवेदकों ने डंप किए गए आयात के कारण घरेलू उद्योग को हुए नुकसान के संबंध में प्रथम दृष्टया सबूत दिए हैं। संबंधित देश से होने वाले आयात की मात्रा में पूर्ण और सापेक्ष, दोनों ही तरह से वृद्धि हुई है। यह आयात घरेलू उद्योग की कीमतों से कम कीमत पर हो रहा है और उनकी कीमतों पर नकारात्मक प्रभाव डाल रहा है। आवेदक का दावा है कि उत्पादन और बिक्री के मामले में उनके प्रदर्शन में गिरावट आई है। संबंधित आयात का घरेलू उद्योग की लाभप्रदता के मानकों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, जिसके परिणामस्वरूप POI (जांच की अवधि) में नुकसान, नकद नुकसान और निवेश पर नकारात्मक रिटर्न हुआ है।

22. आवेदक द्वारा दी गई जानकारी प्रथम दृष्टया यह दर्शाती है कि संबंधित देश से डंप किए गए आयात के कारण घरेलू उद्योग को नुकसान हो रहा है।

(ज) जांच की शुरुआत

23. घरेलू उद्योग द्वारा विधिवत प्रमाणित आवेदन के आधार पर, और डंपिंग तथा उसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को हुए नुकसान को साबित करने वाले आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रथम दृष्टया सबूतों से संतुष्ट होने के बाद, प्राधिकरण एतद्द्वारा अधिनियम की धारा 9A और नियमों के नियम 5 के अनुसार, कथित डंपिंग और उसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को हुए महत्वपूर्ण नुकसान की एंटी-डंपिंग जांच शुरू करता है। इसका उद्देश्य कथित डंपिंग के अस्तित्व, सीमा और प्रभाव का पता लगाना और डंपिंग शुल्क की उस राशि की सिफारिश करना है, जिसे लागू करने पर घरेलू उद्योग को हुए नुकसान को दूर करने के लिए पर्याप्त हो।

(झ) <u>प्रक्रिया</u>

24. इस जांच में एंटी-डंपिंग नियमों के नियम 6 में बताए गए प्रावधानों का पालन किया जाएगा।

(ञ) <u>सूचना की प्रस्तुति</u>

25. सभी संबंधित पक्षों को सेतु पोर्टल (https://setu.dgtr.gov.in) पर अपना पंजीकरण कराना अनिवार्य है। हितबद्ध पक्षकारों की ओर से किए जाने वाले सभी पत्राचार और अनुरोध सेतु पोर्टल पर उनके पंजीकृत नाम और संबद्ध मामले: **एडी/ओआई/011/2026** के अंतर्गत अपलोड की जाएंगी। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अनुरोध का वर्णनात्मक भाग सर्च करने योग्य पीडीएफ/ एमएस-वर्ड प्रारूप में हो और डेटा फ़ाइलें एमएस-एक्सल प्रारूप में हों।

26. संबद्ध देशों के ज्ञात उत्पादकों/ निर्यातकों, संबद्ध देशों की सरकारों को भारत स्थित उनके दूतावासों के माध्यम से, तथा भारत में उन आयातकों और उपयोगकर्ताओं को, जिनका विचाराधीन उत्पाद से संबद्ध होना ज्ञात है, अलग से सूचित किया जा रहा है; ताकि वे इस जांच शुरुआत अधिसूचना में उल्लिखित समय-सीमा के भीतर सभी संगत जानकारी प्रस्तुत कर सकें। ऐसी समस्त जानकारी उसी प्रारूप और तरीके से प्रस्तुत की जानी चाहिए, जैसा कि इस जांच शुरुआत अधिसूचना, नियमों और प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए लागू व्यापार नोटिसों में निर्धारित किया गया है।

27. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी, इस जांच शुरुआत अधिसूचना, नियमों और प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए लागू व्यापार नोटिसों में निर्धारित प्रारूप और तरीके से, तथा इस

जांच शुरुआत अधिसूचना में उल्लिखित समय-सीमा के भीतर, वर्तमान जांच से संबंधित कोई भी अनुरोध दे सकता है।

28. प्राधिकारी के समक्ष कोई भी गोपनीय प्रस्तुति देने वाले किसी भी पक्षकार के लिए यह अनिवार्य है कि वह उसी प्रस्तुति का एक अगोपनीय पाठ अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराए।

29. हितबद्ध पक्षकारों को आगे यह भी सलाह दी जाती है कि वे इस जांच से संबंधित किसी भी अद्यतन जानकारी के लिए, व्यापार उपचार महानिदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट www.dgtr.gov.in और सेतु पोर्टल (https://setu.dgtr.gov.in) पर नियमित रूप से नज़र रखें। हितबद्ध पक्षकारों को यह निर्देश दिया जाता है कि वे संबद्ध जांच में होने वाले आगामी घटनाक्रमों से अवगत रहने के लिए, तथा प्रश्नावली प्रारूपों, पीसीएन कार्यप्रणाली, पीसीएन चर्चा/ बैठक की समय अनुसूची, मौखिक सुनवाई की सूचना, शुद्धिपत्र, संशोधन अधिसूचनाओं और ऐसी ही अन्य जानकारियों के संबंध में समय-समय पर जारी किए जाने वाले नोटिसों की जानकारी प्राप्त करने हेतु, डीजीटीआर की वेबसाइट (https://www.dgtr.gov.in/) पर नियमित रूप से नजर रखें।

(ट) <u>समय सीमा</u>

30. इस जांच से जुड़ी कोई भी जानकारी SETU पोर्टल (https://setu.dgtr.gov.in) पर रजिस्टर्ड नाम और संबंधित केस AD (OI)-034/2026 के तहत अपलोड की जानी चाहिए। हर सबमिशन के दोनों वर्शन - कॉन्फिडेंशियल वर्शन (CV) और नॉन-कॉन्फिडेंशियल वर्शन (NCV) - को तय कॉलम में अपलोड करना ज़रूरी है। यह काम उस तारीख से 37 दिनों के भीतर किया जाना चाहिए जब अथॉरिटी घरेलू इंडस्ट्री द्वारा दायर एप्लीकेशन का नॉन-कॉन्फिडेंशियल वर्शन सेतु पोर्टल पर सर्कुलेट करे या AD रूल्स, 1995 के नियम 6(4) के अनुसार एक्सपोर्ट करने वाले देश के संबंधित डिप्लोमैटिक प्रतिनिधि को भेजे। अगर तय समय सीमा के भीतर कोई जानकारी नहीं मिलती है या मिली जानकारी अधूरी है, तो अथॉरिटी रिकॉर्ड पर मौजूद तथ्यों और AD रूल्स, 1995 के अनुसार अपनी फाइंडिंग्स दर्ज कर सकती है।

31. सभी इच्छुक पार्टियों को सलाह दी जाती है कि वे इस मामले में अपनी रुचि (रुचि की प्रकृति सहित) बताएं और इस नोटिफिकेशन में बताई गई समय सीमा के भीतर केवल SETU पोर्टल के माध्यम से अपने प्रश्नावली (questionnaire) के जवाब फाइल करें।

32. PUC/PCN मेथोडोलॉजी के दायरे पर कमेंट्स फाइल करने के लिए 15 दिन की अवधि, इस शुरुआती नोटिफिकेशन के पैरा 30 में बताई गई समय सीमा के साथ-साथ चलेगी।

33. PUC/PCN में बदलाव के कारण समय बढ़ाना: अगर अथॉरिटी बाद के नोटिस के माध्यम से PUC और PCN में बदलाव करती है - जो पहले प्रस्तावित नहीं थे या शुरुआती नोटिफिकेशन से अलग हैं - तो 15 दिन का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। यह 15 दिन का अतिरिक्त समय बदले हुए PUC और PCN के ऐसे नोटिफिकेशन की तारीख से दिया जाएगा। इस पैराग्राफ में बताया गया 15 दिन का अतिरिक्त समय उन मामलों में लागू नहीं होगा जहां जांच शुरू होने के बाद PUC और PCN मेथोडोलॉजी में कोई बदलाव नहीं होता है। AD रूल्स के नियम 7(4) के अनुसार, असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर, 15 दिन के अतिरिक्त समय (यदि दिया गया हो) से आगे और समय बढ़ाने के अनुरोधों पर आम तौर पर विचार नहीं किया जाएगा।

34. समय-सीमा बढ़ाने के लिए कोई भी अनुरोध संबंधित पक्षों द्वारा SETU पोर्टल के माध्यम से, ऊपर पैराग्राफ 30 में बताई गई मूल समय-सीमा से कम से कम एक दिन पहले जमा किया जाना चाहिए। इस समय के बाद जमा किए गए अनुरोधों पर विचार नहीं किया जाएगा।

(ठ) <u>गोपनीय आधार पर सूचना की प्रस्तुति</u>

35. जहां इस जांच में कोई भी पक्षकार प्राधिकारी के समक्ष गोपनीय प्रस्तुतियां करता है या गोपनीय आधार पर जानकारी प्रदान करता है, तो उस पक्षकार को पाटनरोधी नियमावली के नियम 7(2) के अनुसार और इस संबंध में प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए प्रासंगिक व्यापार नोटिसों के अनुरूप, ऐसी जानकारी का एक अगोपनीय पाठ भी साथ ही प्रस्तुत करना आवश्यक है। उपरोक्त का पालन न किए जाने पर उत्तरों/ अनुरोधों को अस्वीकार किया जा सकता है।

36. जो पक्षकार प्राधिकारी के समक्ष कोई भी अनुरोध (जिसमें उसके साथ संलग्न परिशिष्ट/ अनुलग्नक भी शामिल हैं) करते हैं, जिसमें प्रश्नावली के उत्तर भी शामिल हैं, तो उन्हें गोपनीय और अगोपनीय पाठ अलग-अलग प्रस्तुत करना आवश्यक है।

37. ऐसे अनुरोधों के प्रत्येक पृष्ठ के शीर्ष पर स्पष्ट रूप से "गोपनीय" या "अगोपनीय" के रुप में अंकित होना चाहिए। प्राधिकारी को किया गया कोई भी अनुरोध जिस पर ऐसा

अंकन नहीं है, उसे प्राधिकारी द्वारा "अगोपनीय" जानकारी माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे अनुरोधों का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे।

38. गोपनीय पाठ में वह समस्त जानकारी शामिल होगी जो गोपनीय प्रकृति की है, और/अथवा ऐसी अन्य जानकारी शामिल होगी, जिसके लिए ऐसी जानकारी का प्रदाता गोपनीय होने का दावा करता है। जिस जानकारी के बारे में गोपनीय प्रकृति की होने का दावा किया जाता है, या जिस जानकारी पर अन्य कारणों से गोपनीयता का दावा किया जाता है, उस जानकारी के प्रदाता को दी गई जानकारी के साथ एक उचित कारण विवरण भी देना आवश्यक है कि ऐसी जानकारी का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता।

39. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दायर की गई जानकारी का अगोपनीय पाठ, गोपनीय पाठ की ही एक प्रतिकृति होनी चाहिए, जिसमें गोपनीय जानकारी को अधिमानतः अनुक्रमित किया गया हो या हटा दिया गया हो (जहां अनुक्रमण संभव न हो), और ऐसी जानकारी को, जिस पर गोपनीयता का दावा किया गया है, उचित और पर्याप्त रूप से सारांशित किया जाना चाहिए।

40. अगोपनीय सारांश इतना विस्तृत होना चाहिए कि गोपनीय आधार पर दी गई जानकारी के मूल तत्व की उचित समझ बन सके। तथापि, असाधारण परिस्थितियों में, गोपनीय जानकारी प्रस्तुत करने वाला पक्षकार यह इंगित कर सकता है कि ऐसी जानकारी का सारांश बनाना संभव नहीं है; ऐसे में, नियमावली, 1995 के नियम 8 के अनुसार और प्राधिकारी द्वारा जारी उचित व्यापार नोटिसों के अनुरूप, कारणों का एक विवरण जिसमें कि पर्याप्त और उचित स्पष्टीकरण हो कि ऐसा सारांश क्यों संभव नहीं है, प्राधिकारी की संतुष्टि के लिए प्रदान किया जाना चाहिए।

41. हितबद्ध पक्षकार, दस्तावेज़ों के अगोपनीय पाठ के वितरण की तारीख से 7 दिनों के भीतर, घरेलू उद्योग द्वारा गोपनीयता के संबंध में किए गए दावों पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत कर सकते हैं।

42. प्राधिकारी, प्रस्तुत की गई जानकारी की प्रकृति की जांच करने के बाद, गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते है। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध उचित है, या यदि जानकारी प्रदान करने वाला पक्षकार या तो जानकारी को सार्वजनिक करने के लिए अनिच्छुक है, अथवा उसे सामान्यीकृत या

सारांश रूप में प्रकट करने के लिए अधिकृत नहीं करना चाहता है, तो प्राधिकारी ऐसी जानकारी की अनदेखी कर सकते है।

43. कोई भी ऐसा अनुरोध, जिसके साथ में उसका कोई सार्थक अगोपनीय पाठ संलग्न न हो, अथवा नियमावली के नियम 8 और प्राधिकारी द्वारा जारी उपयुक्त व्यापार सूचनाओं के अनुसार गोपनीयता के दावे के संबंध में कोई पर्याप्त और उचित कारण का विवरण प्रस्तुत न किया गया हो, उसे प्राधिकारी द्वारा रिकार्ड में दर्ज नहीं किया जाएगा।

44. प्राधिकारी, प्रदान की गई जानकारी की गोपनीयता की आवश्यकता से संतुष्ट होने और उसे स्वीकार करने के उपरांत, ऐसी जानकारी प्रदान करने वाले पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना, उसे किसी भी अन्य पक्षकार के समक्ष प्रकट नहीं करेंगे।

(ड) <u>सार्वजनिक फ़ाइल का निरीक्षण</u>

45. किसी भी हितबद्ध पक्षकार द्वारा किए गए अनुरोधों के सभी अगोपनीय पाठ अन्य हितबद्ध पक्षकारों के लिए सेतु पोर्टल पर उनके संबंधित लॉगिन के माध्यम से सुलभ होंगे।

(ढ) <u>असहयोग</u>

46. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर या इस जांच शुरुआत अधिसूचना में प्राधिकारी द्वारा निर्धारित की गई निर्दिष्ट अवधि के भीतर आवश्यक जानकारी प्रदान नहीं करता है या पत्राचार के माध्यम से प्रदान की गई आगे की समय अवधि के भीतर जांच में महत्वपूर्ण रूप से बाधा उत्पन्न करता है, तो प्राधिकारी ऐसे हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और साथ ही उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणामों को दर्ज कर सकते हैं तथा केंद्र सरकार को ऐसी यथाउपयुक्त सिफारिशें कर सकते हैं।

(अमिताभ कुमार)
निर्दिष्ट प्राधिकारी

Digitally signed by
Amitabh Kumar
Date: 23-06-2026
16:18:18